

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सरकार के अपर सचिव-सह-
मुख्य निगरानी पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
कृषि विभाग/भवन निर्माण विभाग/सहकारिता विभाग/
शिक्षा विभाग/ऊर्जा विभाग/वन एवं पर्यावरण विभाग/
वाणिज्य-कर विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/
स्वास्थ्य विभाग/गृह विभाग/गृह (आरक्षी) विभाग/
गृह (कारा) विभाग/उद्योग विभाग/श्रम संसाधन विभाग/
पंचायती राज विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/पथ निर्माण विभाग/
ग्रामीण विकास विभाग/परिवहन विभाग/
नगर विकास एवं आवास विभाग/जल संसाधन विभाग/
बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना ।
प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर/सारण/मुंगेर एवं मगध, गया ।
जिला पदाधिकारी, भागलपुर/लखीसराय/नवादा एवं सारण ।

पटना-15, दिनांक 24 मार्च, 2014

विषय :- निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के काण्डों में वर्ष-2006 से 2013 तक सजायापता अभियुक्तों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना द्वारा दिनांक 20.03.14 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के कुल-104 काण्डों में वर्ष-2006 से वर्ष-2013 तक कुल-146 सजायापता अभियुक्तों की सूची उपलब्ध करायी गयी है जिसे सामान्य प्रशासन विभाग के वेवसाईट पर अपलोड कर दिया गया है । अनुरोध है कि विभाग की वेवसाईट से उक्त सूची डाउनलोड कर सजायापता सरकारी सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें ।

ज्ञातव्य है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-20 के अनुसार न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर सरकारी सेवक को प्रस्तावित शास्ति पर अभ्यावेदन का अवसर देते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा शास्ति अधिरोपित किया जा सकता है ।

अनु.-यथोक्त (कुल पृष्ठ-09) ।

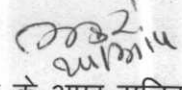
विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव-सह-
मुख्य निगरानी पदाधिकारी ।

कृ.पृ.उ. 2/-

ज्ञापांक-13/विविध-01-04/2014सा.....108...../पटना-15, दिनांक मार्च, 2014

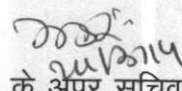
प्रतिलिपि :- निगरानी विभाग, बिहार/निगरानी (अन्वेषण) ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।



सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-13/विविध-01-04/2014सा.....108...../पटना-15, दिनांक मार्च, 2014

प्रतिलिपि :- आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को इस आशय से प्रेषित कि इसे सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के वेवसाईट पर डालने की कृपा करें ।



सरकार के अपर सचिव ।

वर्ष 2006 से 2013 तक निगरानी कांडों में सजायपता व्यक्तियों की सूची :-

वाद की संख्या	केस नं०	विषय	सजा	सजा की तिथि	संबंधित विभाग	वादों में शामिल लोक सेवक एवं गैर लोक सेवकों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	29/88	मो० हसन इमाम, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कृषि विभाग	एक वर्ष सजा, 1000/- रू० जुर्माना	08.06.2001	कृषि विभाग	1	
2	18/83	शंकर दयाल, जन सेवक, पंचायती राज	सजा	30.11.2003	कृषि विभाग	2	
3	05/08	श्री रामवचन सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड फलका, कटिहार	धारा-7 में 1 वर्ष कारावास 3000/-रू० जुर्माना 13 (1) (डी) में 1 वर्ष कारावास 3000/-रू० जुर्माना	11/12/2012	कृषि विभाग	3	
4	29/86	6) श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रशाखा कृषि पदाधिकारी, लखिसराय	सभी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा	21-12-10	कृषि विभाग	4	
1	47/91	श्री जितेन्द्र मोहन, कार्यालय सहायक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना	दो वर्ष एवं 5000/-रू० जुर्माना	7/5/2010	बिहार लोक सेवा आयोग	1	
1	01/83	श्री रविभूषण प्रसाद एवं अन्य, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, भवन अचल, दरभंगा	तीन वर्ष की सजा एवं जुर्माना की सजा	24-09-10	भवन निर्माण विभाग	1	
1	32/92	बिरेन्द्र कुमार, अवर निबंधक, सहकारिता	सजा	20.12.99	सहकारिता	1	
1	07/87	महेश पाण्डेय, शिक्षा निरीक्षक, शिक्षा विभाग	सजा	13.09.95	शिक्षा विभाग	1	
2	23/86	श्री मुद्रीका राय प्रभाकर, प्रधानाध्यापक, शिक्षा विभाग, मध्य विद्यालय, बेलाउर भोजपुर	एक वर्ष एवं 1000/- रू० जुर्माना	26-06-07	शिक्षा विभाग	2	
3	01/96	श्री रामजी सिंह, प्रधान लिपिक, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय, पटना	एक वर्ष एवं 500/-रू० जुर्माना	29-11-08	शिक्षा विभाग	3	
4	33/07	श्री ओम प्रकाश, प्रखंड शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी, कैमूर, भभूआ	धारा-7 में एक वर्ष एवं धारा-13 (1) (डी) में एक वर्ष छः महीना का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक धारा में 5000-5000 रू० का जुर्माना	24-02-11	शिक्षा विभाग	4	